ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Closure of Loss Making NTC Mills

*201. SHRIMATI VANGA GEETHA:†
SHRIMATI BIMBA RAIKAR:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) Whether Government have decided to close down 22 loss making National Textile Corporation (NTC) mills in Maharashtra;

(b) if so, how money will be arranged to pay the workers compensation, VRS and other terminal benefits; and

(c) the scheme chalked out for other NTC mills in India?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the Rehabilitation Schemes approved by BIFR for NTC (South Maharashtra) and NTC (Maharashtra North), 18 loss-making mills out of a total of 35 mills in the State of Maharashtra have been closed. The remaining 17 mills are slated for revival under the scheme.

(b) NTC has mobilised Rs. 644 Cr by floating Government Guaranteed Bonds for paying VRS compensation and other terminal benefits to the 14,500 employees who opted for VRS in Maharashtra.

(c) Rehabilitation Schemes have been approved by Government/BIFR for reviving 53 mills and to close down 66 unviable mills of NTC after giving VRS benefits to the affected employees.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Mr. Chairman, Sir, in our country the weavers are now the least paid in the world, and, are getting only Rs. 16 per hour. Sir, from January, 2005, the restrictions by the WTO on textiles will be removed. This will give an impetus to our weavers, and, opportunities for more employment generation and exporting textiles to any part of the world. Sir, will the Government take this opportunity to rehabilitate the weavers-some of the weavers have committed suicide-by opening all the

†Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Vanga Geetha.

closed National Textile Corporation mills so that the next kin of those weavers can get job opportunities?

श्री शंकर सिंह वाघेला: चैयरमैन सर, यह प्रश्न दूसरे मतलब का है। यह स्ट्रिक्टली क्लोज्ड मिल्स के बारे में या रिवायवल के बारे में महाराष्ट्र के संदर्भ में है, लेकिन जब आप ने विवरण के बारे में पूछा है। हो सकता है हैंडलूम सेक्टर्स में कहीं-न-कहीं ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन एन॰टी॰सी॰ मिल में ऐसी स्थिति नहीं बनी है क्योंकि एन॰टी॰सी॰ के 119 में से 66 क्लोज्ड हैं। उन में सब को हम ने वी॰आर॰एस॰ दिया है और काफी कुछ दिया है। They are happy now. उन में 53 मिल्स जो बाकी हैं, उस में अगर महाराष्ट्र का ब्रेकअप आप पूछना चाहेंगी तो मैं कहूंगा, लेकिन टैपर मिलों के बारे में हम जरूर चिंतित हैं कि उन का कैसे रिवायवल कर के उन को और अच्छी सुविधा दी जाए।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, my question is really concerned about the weavers for getting more employment opportunities, and, that is why I wanted to know it from the hon. Minister. Sir, I would like to know from the hon. Minister. What is the number of NTC mills that are functioning; what is the number of mills that are making profits; what is the number of sick NTC mills; and, what are the measures taken, or, being taken to make them profit-making?

श्री शंकर सिंह वाघेला: आप का दूसरा प्रश्न अच्छा है जो कि इस प्रश्न से संबंधित है। सर, एन॰टी॰सी॰ की 119 मिलें अभी हमारे पास हैं, इन में 66 यानी 65 प्लस 1 हम पांडिचेरी गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं। वे टोटली क्लोज्ड हैं। और जो मिलें क्लोज हैं, इन सब में तकरीबन इनको कुल मिलाकर 119 मिलों का, 10 हजार करोड़ से ज्यादा लॉस हुआ है। फिर भी हमने बांड्स लेकर, तकरीबन 19 सौ करोड़ रुपये के बांड्स लेकर, 66 क्लोज्ड मिल्स का हमने वी॰आर॰एस॰ दे दिया है। चेयरमैन सर, 53 जो बची हैं उनमें भी हर साल 1200 करोड़ का लॉस हो रहा है। 900 करोड़ रुपये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के जाते हैं, 300 करोड़ के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और तनख्वाह उसमें देनी है। इसलिए आज हमारे पास 53 मिल्स हैं, वे सब लॉस मेंकिंग हैं। इसलिए इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हर साल 1200 करोड़ का हिसाब कहां से लाना है? जनता के पगार के पैसे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे स्कीम के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि इसमें इम्प्लॉईज का, लेबरर्स का, कोई प्रॉब्लम न हो।

श्री दत्ता मेघे: सर, मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए। (व्यवधान)

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, like Mumbai, we have got a number of sick and big mills, with vast area, in Karnataka also. So, I would like to ask the hon. Minister whether he is thinking of selling these mills as they have done in Mumbai. As it has happened in Mumbai, in Centaur Hotel case, will the Government sell the land to the builders, or, will the land be utilised for the sake of poor people of small-scale industry and for the benefit of poor people?

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन साहब, मैडम का ऐसा प्रश्न है कि सेन्टोर होटल में जो हुआ था, वह मैं नहीं समझता कि हमारी यह इंडस्ट्री ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप जमीन का जवाब दीजिए।

श्री शंकर सिंह वाघेला: महाराष्ट्र, नॉर्थ और साउथ महाराष्ट्र में 9 और 8 ऐसी मिलें हैं। महाराष्ट्र नॉर्थ में 8 है, महाराष्ट्र साउथ में 9 हैं , जो कि बंद हैं। बाकी जो हैं, क्लोज हुई हैं, वे 10 और 8 हैं। ये भी लॉस मेकिंग हैं। कुल 35 मिलें महाराष्ट्र में हैं। सर, इसमें सिस्टम है राज्य सरकार का। मैंने जब चार्ज लिया तो शिंदे साहब महाराष्ट्र के सी॰एम॰ थे। मैंने उनसे कहा कि इन मिलों में हमने 1800 करोड़, 1900 करोड़ रुपये के बॉंड्स लिए हैं, वे एक्सेस लैंड बेच कर फिर वापस देने हैं, तो आप इसको क्लीयर करिए। राज्य सरकार को इसको क्लीयर करना है। और बी॰आई॰एफ॰आर॰ में इसका कमिटमेंट भी होता है कि हम क्लियर करेंगे। इसके हिसाब से मुम्बई में 7 मिलें क्लीयर हुई हैं। वन-थर्ड सिस्टम जो है, वन-थर्ड महाराष्ट्र महाडा को जाएगी, वन-थर्ड लोकल बी॰एम॰सी॰ को जाएगी, वन-थर्ड हमारे पास रहेगी। इस हिसाब से 7 में से 2 मिलें, एक महाडा को गयी हैं और एक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गई है। चेयरमैन सर, 5 हमारे पास हैं। इन सब के लिए हमने कंसल्टेंट्स नियुक्त किये हैं। पूरी ट्रांस्पैरेंसी के साथ मुम्बई को शोभा देने वाले टेक्स्टाइल पोस्चर के साथ, ये मिलें बिल्डर्स को नहीं दी जायेंगी। ये मिलों में अपने हिसाब से एन॰टी॰सी॰ को मार्गदर्शन देंगे कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ऐसा सोचकर पूरे ट्रांसस्पैरेंसी के साथ डीलिंग हो रही है।

श्री दत्ता मेघे: सर, यह महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ सवाल है। महाराष्ट्र के जो मजदूर हैं अभी भी दस साल, बारह साल हुए हैं, उनको वी॰आर॰एस॰ के पैसे नहीं मिले। आपने कहा 684 करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। लेकिन जो मिल मालिक हैं, वे जमीन बेच कर पैसा देना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मिल के जो मजदूर हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में जिनका बकाया है, ऑफिसियली बकाया है, वह जल्दी-से-जल्दी आप कब देने वाले हैं? वह जमीन बेचेंगे, बेचेंगे, लेकिन जो 684 करोड़ है, इसमें से तो कम से कम पहला हफ्ता तो उन लोगों को दे दें।

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन सर, ये दो हिस्सों में हैं। एन॰टी॰सी॰ इम्प्लॉईज, एन॰टी॰सी॰

का जमीन, प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट मिल्स, वह अलग हिस्सा है। महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में जो 66 क्लोज्ड मिल्स हैं, इन सब को, एक भी लेबर को, बिना वी॰आर॰एस॰ के हमने नहीं छोड़ा है। आपने जो प्राइवेट पार्टी के बारे में कहा। इसमें टी॰डब्ल्यू॰आर॰एफ॰ जो स्कीम है, जो प्राइवेट मिल्स के बारे में है। इनके बारे में जो हमने 2002 से लागू करना था, वह यह कि इनका वर्ष 1993 से जो 2500/- रुपए तनख्वाह वाला बेस था, बढ़ाकर 3500/- तक लाना था, वह अंडर ओब्जरवेशन हमारी स्कीम में है। आने वाले दिनों में प्राइवेट मिल के मजदूर को भी टी॰डब्ल्यू॰आर॰एफ॰ स्कीम में लाने के लिए अभी हम इसे चर्चा में लाकर, इनको जो सुविधा देनी है, वह भारत सरकार, टैक्सटाइल मिनिस्टरी देगी।

SHRI MURLI DEORA: Sir, I would like to know from the Hon. Minister whether there is any definite policy of the Government when they are allowing the sale of the NTC mills. And what are they going to do with the proceeds realised on selling the land?

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन सर, यह ओपेन फैक्ट है कि एक्सेस जमीन को बेचकर 1800 करोड़ रुपए या 1900 करोड़ रुपए के बांड्स हमने रीपे करना हैं। इसमें तकरीबन हर साल इसमें हमको तकरीबन 150 करोड़, 200 करोड़ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलाकर इनको वापस देना पड़ता है। रहा मुम्बई का सवाल, इसमें पूरी ट्रांसपेरेन्सी के साथ हमने कंसलटेंट्स को इन्वाइट किया है और कंसलटेंट्स या बिल्डर या जो भी होगा, उनके साथ मिलकर, एनटीसी के साथ मिलकर जो भी प्रोजेक्ट रखना चाहेंगे, उसमें हाइएस्ट वेल्यू जो हमको दे, यानि कि एक्स मिल है, इसकी कीमत यह है तो वह डवलप करने वाले लोग हमारे कंसलटेंट्स से मिलकर वहीं पब्लिकली, सब के साथ इंटरनेट पर यह चीज मिलेगी। मैं समझता हूं कि टैक्सटाइल पोस्चर रखते हुए मिलों का डिस्पोजल होगा। मुम्बई में पांच मिलें अभी क्लीयर हुई हैं।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मुम्बई के मध्य क्षेत्र में ज्यादातर मिलें हैं और आज मिलों की कब्र पर शॉपिंग-माल बन रहे हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर का कोई डवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए जो बार-बार आप ट्रांसपेरेन्सी की बात कर रहे हैं, जो सवाल बिंबा जी ने किया, मुरली जी ने भी किया, बिल्कुल उसी तरह का सवाल मेरा भी है, ट्रांसपेरेन्सी में विश्वास है, लेकिन यह जो पांच मिलें रह गई हैं अभी बेचे जाने के लिए, इनके लिए क्या किसी प्रकार का रिजर्वेशन है या ओपेन मार्केट में बिल्डर्स लेकर के फिर से शॉपिंग माल बनाकर के उसी तरह से मुम्बई को और क्राउडेड कर देंगे? मैं रिजर्वेशन के संदर्भ में पूछना चाह रहा हूं कि इनको किसको बेचे जाने की बात हो रही है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन साहब, इसमें हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गए थे। सबका अभिप्राय यह था कि इन मिलों को फिर से मिल के रूप में चालू करने का प्रोजेक्ट रखना तो ठीक नहीं होगा और शहर के मध्य में फिर मिल चालू होगी तो वह तो ठीक नहीं होगा। अभिप्राय सबका

यही था कि इस मिल को जिस सिस्टम से, उसकी जमीन को बेचना है, वह आप बेच डालें। इसमें हमको पूर्ण अधिकार है जैसे भी बेचना है। इसमें फुल ट्रासपेरेन्सी के साथ बेचना है, लेकिन जहां तक मुम्बई का है, अर्बन इलाका है, शहर के मध्य में है, इसलिए बड़े बड़े माल या मल्टी-स्टोरीज हों, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। टैक्सटाइल पोस्चर के साथ इसमें बहुत हैंडीक्राफ्ट माल हो, फाइबर मार्केट हो, क्लॉथ मार्केट हो, बड़े बड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हो, इस जमीन का अच्छा उपयोग हो, जैसे यहां दिल्ली में प्रगति मैदान है, वैसा ही मुम्बई में भी कोई मैदान हो, जिसमें मशीनरी रखना हो या मशीनरी शो करना हो, वह कर सके, व्यापार करना हो वह कर सके। इस हिसाब से यह प्रोजेक्ट हमारी सीधी देखरेख में इंपलीमेंट होंगे। इसमें कोई प्राइवेट बिल्डर मकान बनाकर या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके सीधा मुनाफा करे, उस हक में हम नहीं हैं।

Textiles Exports

*202. SHRI B.J. PANDA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had made a statement that our exports will double in the next two years quelling fears that cheaper Chinese products will hit the Indian industry;

(b) how far we will benefit from the free global trade in the textile market; and

(c) what is our action plan to put thrust on making the "Made in India" brand popular in the world market?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. There is a general perception that India's textile exports would increase in the post quota regime starting from 1st January 2004. According to a recent study by CRISIL (commissioned by Indian Cotton Mills Federation), the India's textile and clothing industry has the potential to double the country's share of the global textiles and clothing market to 6 per cent, implying export earnings of US$ 40 billion by 2010.

The free global trading regime would result in increased international trade in textiles thus providing greater export opportunities for the indigenous textile industry. At the same time, it will expose the domestic